नियोजित विकास की राजनीति

इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न – उत्तर सहित। पहले खुद हल करने की कोशिश करो, फिर उत्तर मिलाओ।

अभ्यास प्रश्न-उत्तर (हर टॉपिक से)

» विकास को लेकर राजनीतिक निर्णय और टकराव

प्रश्न 1 (आसान). अगर सरकार किसी जंगल को काटकर कोई बड़ा उद्योग लगाना चाहती है, तो किन-किन समूहों के बीच टकराव हो सकता है?

उत्तर – सरकार (विकास के लिए), स्थानीय आदिवासी/ग्रामीण (घर और आजीविका के लिए), पर्यावरणविद (जंगल बचाने के लिए)।

प्रश्न 2 (आसान). विकास के फैसले अक्सर राजनीतिक क्यों होते हैं?

उत्तर – क्योंकि इनमें कई समूहों के अलग-अलग हितों को समझना और उनके बीच संतुलन बनाकर निर्णय लेना होता है, जो जनता के प्रतिनिधियों का काम है।

प्रश्न 3 (मध्यम). आपके हिसाब से, उड़ीसा में इस्पात संयंत्र के मामले में सरकार को किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था?

उत्तर – स्थानीय आदिवासियों के पुनर्वास और आजीविका की सुरक्षा पर, साथ ही पर्यावरण के नुकसान को कम करने पर, और अंत में राज्य के आर्थिक विकास के लाभों पर।

प्रश्न 4 (कठिन). क्या कभी ऐसा हो सकता है कि विकास का कोई निर्णय किसी के लिए भी टकराव पैदा न करे? अपने उत्तर का कारण भी बताओ।

उत्तर – ऐसा बहुत मुश्किल है। विकास के हर निर्णय में किसी न किसी समूह का हित प्रभावित होता ही है। चाहे वह छोटी सी सड़क बनाना हो या बड़ा बाँध, हमेशा कोई न कोई पक्ष प्रभावित होता है, इसलिए टकराव की संभावना रहती है। हाँ, अगर सबके हितों का ध्यान रखा जाए और उचित समाधान दिया जाए, तो टकराव को कम ज़रूर किया जा सकता है।

» वामपंथ और दक्षिणपंथ की अवधारणा

प्रश्न 5 (आसान). जो लोग 'गरीबों की मदद के लिए ज़्यादा सरकारी योजनाएँ' चाहते हैं, वे वामपंथी हैं या दक्षिणपंथी?

उत्तर – वामपंथी

प्रश्न 6 (आसान). कौन-सी विचारधारा 'बाज़ार को आज़ादी' देने की बात करती है?

उत्तर – दक्षिणपंथी

प्रश्न 7 (मध्यम). अगर कोई पार्टी कहती है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए और सरकारी स्कूलों की संख्या कम करनी चाहिए, तो उसकी सोच वामपंथी होगी या दक्षिणपंथी?

उत्तर – दक्षिणपंथी, क्योंकि वे शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप कम करके निजीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं।

प्रश्न 8 (कठिन). भारत ने आज़ादी के बाद शुरुआती दशकों में विकास का कौन सा रास्ता अपनाया था? क्या वह पूरी तरह से वामपंथी था या दक्षिणपंथी?

उत्तर – भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था, जिसमें सरकारी नियंत्रण (वामपंथ) और निजी क्षेत्र (दक्षिणपंथ) दोनों की भूमिका थी। हालाँकि, शुरुआत में सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा था, जो वामपंथी झुकाव दर्शाता है।

» विकास की धारणाएँ और मॉडल

प्रश्न 9 (आसान). आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के कितने मुख्य मॉडल थे?
उत्तर – दो मुख्य मॉडल थे।

प्रश्न 10 (आसान). किस मॉडल में सरकार का अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप होता है?
उत्तर – उदारवादी-पूंजीवादी मॉडल में।

प्रश्न 11 (मध्यम). सोवियत संघ ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था?
उत्तर – सोवियत संघ ने समाजवादी मॉडल अपनाया था।

प्रश्न 12 (कठिन). बताइए, 'विकास' की धारणा क्यों अलग-अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है?
उत्तर – क्योंकि हर व्यक्ति या समूह की ज़रूरतें, प्राथमिकताएँ और परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए जो एक के लिए 'विकास' है, वो दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता है।

» योजना आयोग की स्थापना और भूमिका

प्रश्न 13 (आसान). योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर – मार्च 1950

प्रश्न 14 (आसान). योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था थी या नहीं?
उत्तर – नहीं, यह एक गैर-संवैधानिक संस्था थी, जिसे सरकारी प्रस्ताव से बनाया गया था.

प्रश्न 15 (मध्यम). योजना आयोग की स्थापना के पीछे क्या मुख्य कारण थे?
उत्तर – आज़ादी के बाद भारत के नियोजित आर्थिक विकास के लिए एक केंद्रीय संस्था की आवश्यकता थी जो पंचवर्षीय योजनाएँ बना सके और संसाधनों का उचित आवंटन कर सके.

प्रश्न 16 (कठिन). योजना आयोग की भूमिका को एक सलाहकार संस्था के रूप में कैसे समझाया जा सकता है?
उत्तर – यह एक सलाहकार संस्था थी क्योंकि यह अपनी योजनाएँ और सुझाव मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करती थी, और उन सुझावों को लागू करना है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल ही लेता था. यह सीधे तौर पर नीतियाँ लागू नहीं करती थी, बल्कि नीतियाँ बनाने में मदद करती थी.

» नियोजन का विचार और बॉम्बे प्लान

प्रश्न 17 (आसान). आज़ादी के बाद भारत में किस तरह के विकास की ज़रूरत महसूस की गई?
उत्तर – आज़ादी के बाद भारत में नियोजित विकास की ज़रूरत महसूस की गई।

प्रश्न 18 (आसान). बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था?
उत्तर – बॉम्बे प्लान 1944 में तैयार किया गया था।

प्रश्न 19 (मध्यम). बॉम्बे प्लान में सरकार की किस भूमिका पर ज़ोर दिया गया था?
उत्तर – बॉम्बे प्लान में सरकार की औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने की भूमिका पर ज़ोर दिया गया था।

प्रश्न 20 (कठिन). बॉम्बे प्लान ने नियोजन के विचार को कैसे प्रभावित किया, जबकि यह निजी क्षेत्र द्वारा तैयार किया गया था?
उत्तर – बॉम्बे प्लान ने दिखाया कि यहां तक कि निजी क्षेत्र भी यह मानता था कि देश के विकास के लिए सरकार को औद्योगिक निवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इसने नियोजन के विचार को एक व्यापक समर्थन दिया और आज़ादी के बाद भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की नींव रखने में मदद की।

» पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत

प्रश्न 21 (आसान). पंचवर्षीय योजनाओं का विचार भारत ने किस देश से लिया?
उत्तर – सोवियत संघ से।

प्रश्न 22 (आसान). पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी?
उत्तर – 1951 में।

प्रश्न 23 (मध्यम). पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
उत्तर – अगले पांच सालों के लिए देश की आमदनी और खर्च की एक विस्तृत योजना बनाना, ताकि अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के लिए विकास हो सके।

प्रश्न 24 (कठिन). योजना-व्यय और गैर-योजना-व्यय में क्या अंतर है? एक उदाहरण देकर समझाओ।
उत्तर – योजना-व्यय वो खर्च था जो पंचवर्षीय योजना में तय की गई नई प्राथमिकताओं (जैसे नया स्कूल बनाना, नया बांध बनाना) पर होता था। गैर-योजना-व्यय वो था जो हर साल होने वाले रोज़मर्रा के खर्चों (जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, मौजूदा सड़कों का रखरखाव) पर होता था, जिसके लिए कोई नई योजना नहीं बनती थी।

» प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956)

प्रश्न 25 (आसान). प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से किस वर्ष तक चली?
उत्तर – 1951 से 1956 तक।

प्रश्न 26 (आसान). इस योजना में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया?
उत्तर – कृषि क्षेत्र पर।

प्रश्न 27 (मध्यम). प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी बड़ी परियोजना शुरू की गई?
उत्तर – भाखड़ा-नांगल जैसी विशाल बाँध परियोजनाएँ।

प्रश्न 28 (कठिन). के.एन. राज ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में क्या तर्क दिया था?
उत्तर – उन्होंने तर्क दिया था कि अगले दो दशक तक भारत को अपनी विकास की चाल धीमी रखनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुँचे।

» द्वितीय पंचवर्षीय योजना और औद्योगीकरण

प्रश्न 29 (आसान). द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी?
उत्तर – 1956

प्रश्न 30 (आसान). पी.सी. महालनोबिस किस क्षेत्र से संबंधित थे?
उत्तर – अर्थशास्त्र और सांख्यिकी

प्रश्न 31 (मध्यम). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने देसी उद्योगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाया?
उत्तर – सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया।

प्रश्न 32 (कठिन). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज़ोर देने से क्या समस्याएँ पैदा हुईं?
उत्तर – भारत को प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी और उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया, जिससे खाद्यान्न-संकट की आशंका पैदा हुई।

» विकेंद्रीकृत नियोजन: केरल मॉडल

प्रश्न 33 (आसान). विकेंद्रीकृत नियोजन का क्या अर्थ है?
उत्तर – जब योजनाएँ बनाने और निर्णय लेने की शक्ति सिर्फ एक जगह केंद्रित न होकर निचले स्तरों (गाँव, पंचायत) तक बाँट दी जाए।

प्रश्न 34 (आसान). केरल मॉडल में किन प्रमुख क्षेत्रों पर ज़ोर दिया गया?
उत्तर – शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार।

प्रश्न 35 (मध्यम). 'नव लोकतांत्रिक पहल' अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था?
उत्तर – लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल करना, जैसे शत-प्रतिशत साक्षरता अभियान।

प्रश्न 36 (कठिन). कम प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक आधार कमज़ोर होने के बावजूद केरल ने किन सामाजिक सूचकांकों में असाधारण सफलता हासिल की है?
उत्तर – केरल ने शत-प्रतिशत साक्षरता, उच्च आयु प्रत्याशा, कम शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर में असाधारण सफलता हासिल की है, और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ भी मुहैया हैं।

» नीति आयोग: योजना आयोग का प्रतिस्थापन

प्रश्न 37 (आसान). नीति आयोग किस तारीख को अस्तित्व में आया?
उत्तर – 1 जनवरी 2015

प्रश्न 38 (आसान). नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है?
उत्तर – योजना आयोग

प्रश्न 39 (मध्यम). नीति आयोग का पूरा नाम क्या है और यह सरकार के लिए क्या भूमिका निभाता है?
उत्तर – नीति आयोग का पूरा नाम 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था' है। यह सरकार के लिए एक 'थिंक टैंक' (विचारक समूह) की भूमिका निभाता है, यानी नीतियाँ बनाने और सलाह देने का काम करता है।

प्रश्न 40 (कठिन). योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग में राज्यों की भागीदारी किस प्रकार भिन्न है?
उत्तर – योजना आयोग में नीतियाँ मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती थीं और राज्यों को उनका पालन करना होता था। नीति आयोग में राज्यों को नीति-निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है, जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। राज्यों के मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं।

हल किए हुए उदाहरण (step-by-step)

उदाहरण 1. मान लीजिए कि सरकार ने एक नया नियम बनाया कि शहर के बीचों-बीच जो पुराने मकान हैं, उन्हें तोड़कर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। इससे शहर की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, पर उन मकानों में रहने वाले लोगों का क्या होगा?

› पहला कदम: सरकार देखती है कि मॉल से कितना रोजगार मिलेगा और कितना पैसा आएगा।

› दूसरा कदम: वहीं, जो लोग मकानों में रह रहे हैं, वे विरोध करते हैं क्योंकि उनका घर और रोज़गार (अगर दुकानें हों) छिन जाएगा।

› तीसरा कदम: पर्यावरणविद कह सकते हैं कि मॉल बनने से और प्रदूषण बढ़ेगा, या कुछ ऐतिहासिक चीज़ें नष्ट हो सकती हैं।

› चौथा कदम: सरकार को इन सभी 'हितों' (यानी लोगों की ज़रूरतों और चाहतों) को समझना होगा और फिर एक ऐसा राजनीतिक निर्णय लेना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, और नुकसान कम से कम हो। शायद उन्हें मुआवजा देना पड़े या कहीं और जगह देनी पड़े।

› पांचवां कदम: अंतिम निर्णय हमेशा राजनीतिक होता है, क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधियों को सबकी बात सुनकर फैसला लेना होता है।

उत्तर – इस उदाहरण में, सरकार को अर्थव्यवस्था, रोज़गार और विस्थापित लोगों के पुनर्वास के बीच संतुलन साधना पड़ा। यह एक 'विकास को लेकर राजनीतिक निर्णय और टकराव' का सटीक उदाहरण है।

उदाहरण 2. अगर कोई राजनीतिक दल कहता है कि सरकार को सभी बड़े उद्योगों को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए ताकि सभी को नौकरी मिले और कोई अमीर-गरीब का फर्क ना रहे, तो वह किस विचारधारा का समर्थन कर रहा है?

› यहाँ दल चाहता है कि सरकार का अर्थव्यवस्था पर 'नियंत्रण' ज़्यादा हो।

› उसका उद्देश्य 'अमीर-गरीब का फर्क खत्म करना' है, जो सामाजिक न्याय से जुड़ा है।

› ऐसी सोच जहाँ सरकार की भूमिका ज़्यादा हो और समानता पर ज़ोर हो, उसे 'वामपंथ' कहते हैं।

उत्तर – यह दल वामपंथी विचारधारा का समर्थन कर रहा है।

उदाहरण 3. भारत के आज़ादी के समय उपलब्ध दो प्रमुख विकास मॉडल कौन से थे और उनके मुख्य अंतर क्या थे?

› पहला मॉडल था 'उदारवादी-पूंजीवादी मॉडल' – यह ज़्यादातर अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों ने अपनाया था।

› इसमें सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, बाज़ार को खुला छोड़ दिया जाता है, और निजी कंपनियाँ अर्थव्यवस्था चलाती हैं। मुख्य ज़ोर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लाभ पर होता है।

› दूसरा मॉडल था 'समाजवादी मॉडल' – इसे सोवियत संघ ने अपनाया था।

› इसमें सरकार अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रखती है, ताकि संसाधनों का बँटवारा समानता के आधार पर हो और किसी एक के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा न हो। मुख्य ज़ोर सामाजिक समानता और सामूहिक कल्याण पर होता है।

उत्तर – भारत के सामने आज़ादी के समय उदारवादी-पूंजीवादी मॉडल (बाजार-आधारित) और समाजवादी मॉडल (सरकार-आधारित) दो प्रमुख विकल्प थे।

उदाहरण 4. योजना आयोग की स्थापना कब हुई और इसकी प्रमुख भूमिका क्या थी?

› सबसे पहले, हम देखेंगे कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी.

› दूसरा, हम यह समझेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य या भूमिका क्या थी, यानी यह क्या काम करता था.

› स्थापना मार्च 1950 में हुई थी, जैसा हमने पढ़ा है.

› इसकी प्रमुख भूमिका भारत के आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाना और सरकार को सलाह देना था, ताकि देश सही दिशा में आगे बढ़े और सबका भला हो सके.

उत्तर – योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी, और इसकी प्रमुख भूमिका भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाना तथा सरकार को सलाहकार के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करना था.

उदाहरण 5. बॉम्बे प्लान क्या था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?

› पहला कदम: समझना कि 'बॉम्बे प्लान' आज़ादी से पहले, 1944 में भारत के कुछ बड़े उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया था।

› दूसरा कदम: यह एक आर्थिक विकास की योजना थी, जिसमें सरकार की भूमिका पर ज़ोर दिया गया था।

› तीसरा कदम: इसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए ताकि देश का तेज़ी से विकास हो सके।

उत्तर – बॉम्बे प्लान 1944 में भारत के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई एक योजना थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश में सक्रिय भूमिका निभाए ताकि देश का तीव्र आर्थिक विकास हो सके।

उदाहरण 6. पंचवर्षीय योजनाओं के तहत, सरकार के बजट को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया?

› सबसे पहले, यह समझना ज़रूरी है कि 'बजट' का मतलब क्या है। बजट यानी सरकार की आमदनी और खर्च का हिसाब।

› अब जब सरकार 5 साल के लिए योजना बना रही है, तो उसे अपने पूरे खर्च को दो अलग-अलग कैटेगरी में बांटना पड़ा।

› पहला था 'गैर-योजना-व्यय' (Non-Plan Expenditure) - इसमें वो खर्च शामिल थे जो रोज़मर्रा के काम के लिए होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पुलिस का खर्च। ये हर साल होते ही हैं, इनके लिए कोई नई योजना नहीं बनती।

› दूसरा था 'योजना-व्यय' (Plan Expenditure) - इसमें वो खर्च शामिल थे जो उस खास पंचवर्षीय योजना में तय किए गए नए कामों पर होते थे, जैसे नए बांध बनाना, स्कूल खोलना, उद्योग लगाना। ये खास योजना के तहत किए जाते थे।

› तो इस तरह, सरकार ने अपने खर्च को दो हिस्सों में बांटकर पूरे देश के विकास का एक बड़ा नक्शा तैयार किया।

उत्तर – पंचवर्षीय योजनाओं के तहत, सरकार के बजट को 'योजना-व्यय' (Plan Expenditure) और 'गैर-योजना-व्यय' (Non-Plan Expenditure) इन दो मुख्य भागों में बांटा गया था।

उदाहरण 7. प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस क्षेत्र पर था और क्यों?

› पहला कदम: हमें याद रखना होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी, जब देश आज़ाद ही हुआ था।

› दूसरा कदम: उस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का पेट भरना और गरीबी दूर करना।

› तीसरा कदम: विभाजन के बाद कृषि की हालत बहुत खराब थी, इसलिए इस पर तुरंत ध्यान देना ज़रूरी था।

› चौथा कदम: इसीलिए इस योजना का मुख्य जोर 'कृषि' क्षेत्र पर था। इसमें भाखड़ा-नांगल जैसे बड़े बाँध और सिंचाई परियोजनाओं में निवेश किया गया।

› पाँचवां कदम: भूमि सुधारों को भी महत्वपूर्ण माना गया, ताकि ज़मीन का बँटवारा सही से हो सके और उत्पादन बढ़े।

उत्तर – प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर 'कृषि' क्षेत्र पर था क्योंकि देश को गरीबी से निकालना और लोगों को भोजन उपलब्ध कराना सबसे पहली प्राथमिकता थी। विभाजन के कारण कृषि को भारी नुकसान हुआ था, और इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी था।

उदाहरण 8. द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था और इसे किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने तैयार किया था?

› सबसे पहले, यह याद करें कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि था।

› अब सोचें कि उसके बाद देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरत थी - क्या सिर्फ़ खेती से काम चल जाता?

› नहीं, देश को मज़बूत बनाने के लिए बड़े कारखाने और उद्योग चाहिए थे।

› इसलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी उद्योगों (औद्योगीकरण) का विकास था।

› इसे तैयार करने वाले अर्थशास्त्री का नाम पी.सी. महालनोबिस था, जो एक जाने-माने सांख्यिकीविद भी थे।

उत्तर – द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस 'औद्योगीकरण' (भारी उद्योगों का विकास) था, और इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पी.सी. महालनोबिस ने तैयार किया था।

उदाहरण 9. केरल मॉडल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, खासकर 'नव लोकतांत्रिक पहल' के संदर्भ में।

› सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि केरल मॉडल का आधार 'विकेंद्रीकृत नियोजन' है, यानी योजनाएँ केंद्र या राज्य से नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर (गाँव, पंचायत) से बनती हैं।

› दूसरा, इसकी प्रमुख विशेषताएँ शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधारों पर ज़ोर देना है। केरल ने इन क्षेत्रों में बहुत निवेश किया।

› तीसरा, 'नव लोकतांत्रिक पहल' अभियान (1987-1991) केरल मॉडल का एक अहम हिस्सा था। इस अभियान का लक्ष्य लोगों को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल करना था।

› चौथा, इसी पहल के तहत विज्ञान और पर्यावरण जैसे मामलों में शत-प्रतिशत साक्षरता के अभियान चलाए गए, ताकि लोग न केवल पढ़-लिख सकें, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी समझ सकें।

› आखिर में, इस मॉडल ने लोगों को पंचायत, प्रखंड और ज़िला स्तर पर योजनाएँ बनाने में भागीदार बनाया, जिससे वे अपनी स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से विकास कर सकें।

उत्तर – केरल मॉडल विकेंद्रीकृत नियोजन पर आधारित है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया। 'नव लोकतांत्रिक पहल' जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों को स्वयंसेवी संगठनों के ज़रिए योजना निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सीधे शामिल किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास हो सके।

उदाहरण 10. योजना आयोग को कब और किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? इसके दो मुख्य उद्देश्य बताइए।

› पहला, योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को प्रतिस्थापित किया गया।

› दूसरा, इसकी जगह 'नीति आयोग' (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) का गठन किया गया।

› तीसरा, इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक है सरकार के 'थिंक टैंक' (विचारक समूह) के रूप में काम करना।

› चौथा, इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य है राज्यों को विकास संबंधी नीति-निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना, यानी 'सहकारी संघवाद' को बढ़ावा देना।

उत्तर – योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया। इसके मुख्य उद्देश्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करना और राज्यों की सक्रिय भागीदारी से नीति-निर्माण करना हैं।

बोर्ड परीक्षा के लिए ख़ास

• उड़ीसा के इस्पात संयंत्र वाले उदाहरण को अच्छे से समझना, क्योंकि यह अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि कैसे विकास के नाम पर अलग-अलग हित टकराते हैं।

• यह अवधारणा अक्सर 4 या 6 नंबर के प्रश्न में पूछी जाती है जहाँ आपको दोनों की परिभाषा और उनके मुख्य बिंदुओं की तुलना करनी होती है। 'सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन-सा पक्ष लेगा' पर ध्यान देना।

• यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर सीधे पूछा जाता है कि भारत ने आज़ादी के बाद कौन से विकास मॉडल पर विचार किया और क्यों, इसलिए दोनों मॉडलों के मुख्य बिंदुओं को अच्छे से समझ लेना।

• यह प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि भारत की नियोजन नीति की शुरुआत कैसे हुई, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य और कृषि पर उसके ज़ोर को याद रखना बहुत ज़रूरी है।

• केरल मॉडल पर अक्सर 4 या 6 नंबर का सीधा प्रश्न आता है, जहाँ आपको इसकी विशेषताओं और सफलताओं का विस्तार से वर्णन करना होगा। इसके सामाजिक सूचकांकों को याद रखना बहुत ज़रूरी है।

एक नज़र में रिवीज़न

› विकास के निर्णयों में विभिन्न हितों का टकराव, अंतिम निर्णय राजनीतिक।

› वामपंथ: राज्य नियंत्रण, सामाजिक समानता। दक्षिणपंथ: बाज़ार, कम सरकारी दखल।

› विकास धारणा भिन्न, आज़ादी पर उदारवादी-पूंजीवादी/समाजवादी मॉडल विकल्प।

› प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56): कृषि पर जोर, गरीबी उन्मूलन, भूमि सुधार।

› केरल मॉडल: विकेंद्रीकृत नियोजन, शिक्षा-स्वास्थ्य-भूमि सुधार, जनभागीदारी।